रिपोर्टयोग्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन

सिविल अपील नं.4044 ऑफ 2023

[@स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल) नं.12248 ऑफ 2023]

[@डायरी नं. 23042 ऑफ 2011]

आयश मोहम्मद ....अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य ....प्रतिवादीगण

आर 1: हरियाणा राज्य

आर2: पुलिस महानिदेशक (हरियाणा), पंचकुला

आर3: पुलिस महानिरीक्षक, गुड़गांव

आर4: पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक, गुड़गांव

आर5: पुलिस महानिरीक्षक, फरीदाबाद

आर6: पुलिस अधीक्षक, नूह

आर7: पुलिस अधीक्षक, पलवल

निर्णय

अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.....

उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर अंततः पक्षों के लिए विद्वान अधीक्षक को सुना। प्रतिवादीगण का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता के माध्यम से किया जाता है और उन्होंने लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की हैं। न्याय के हित में इन विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में देरी को माफ कर दिया गया। आई.ए 72995/2022 [दोषों को फिर से भरने/ठीक करने में देरी को माफ करने की मांग] की औपचारिक रूप से अनुमति है।

2. अनुमति दी गयी।

3. एकमात्र अपीलकर्ता ने अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 25.04.2011 (इसके बाद "आक्षेपित निर्णय" के रूप में संदर्भित) **[2011 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 4687** आईएलआर **(2012) 2** पी एंड एच **747]** द्वारा चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित) की एक विद्वान खंड पीठ द्वारा 2011 (ओ एंड एम) की लेटर्स पेटेंट अपील No.406 में पारित किए जाने से व्यथित होकर इस न्यायालय का रुख किया है, जिसके तहत विद्वान खंड पीठ ने प्रतिवादी-राज्य द्वारा पसंद की गई अपील को अनुमति दी और विद्वान एकल द्वारा सिविल रिट याचिका नंबर.19128 ऑफ 2006 में पारित 27.01.2010 **[2010 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 1193]** के आदेश को रद्द कर दिया।

<u>वास्तविक तर्क:</u>

4. अपीलकर्ता 15.01.1973 को हरियाणा पुलिस में सिपाही के रूप में शामिल हुआ और 06.12.1993 को हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत हुआ।एक सहायक उप-निरीक्षक बसंत पाल ने अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत की।इसके परिणामस्वरूप विभागीय जांच हुई, जिसमें अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया और हेड कांस्टेबल से कांस्टेबल को वापस करने का आदेश दिया गया। अपीलकर्ता द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, गुड़गांव रेंज के समक्ष उक्त प्रत्यावर्तन आदेश के खिलाफ एक अभ्यावेदन दायर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, पुलिस महानिरीक्षक, गुड़गांव रेंज ने दिनांक 28.04.2001 के आदेश द्वारा एक वेतन वृद्धि को रोकने के लिए प्रत्यावर्तन के आदेश को संशोधित किया। अपीलकर्ता के नियंत्रक अधिकारी ने 11.10.1999 से 31.03.2000 और 01.04.2000 से 29.12.2000 के बीच की अवधि के लिए उसके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की।प्रारंभ में, 01.04.1999 से 31.03.2000 के बीच की अवधि के लिए प्रस्तुत अभ्यावेदन को 19.02.2002 और 27.06.2001 दिनांकित आदेशों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। हालाँकि, 01.04.2000 से 29.12.2000 तक की अवधि से संबंधित अभ्यावेदन को आंशिक रूप से 20.07.2002 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया था। इसके बाद, अपीलकर्ता ने उपरोक्त अवधि के लिए दूसरा समेकित प्रतिनिधित्व वरीयता दी, जिसे 28.01.2005 को स्वीकार कर लिया गया।अपीलकर्ता द्वारा यह दूसरा अभ्यावेदन विद्वान सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) के समक्ष 2002 के सिविल सूट No.168 (06.08.2002 पर दायर) में दिनांकित 27.09.2004 निर्णय के अनुसार था, जिसके तहत एक वेतन वृद्धि को रोक दिया गया था और प्रतिवादीगण को इसे जारी करने का निर्देश दिया गया था।हालाँकि, प्रतिकूल टिप्पणियों

को हटाने के लिए उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया था, फिर भी विद्वान दीवानी न्यायालय द्वारा एक नए प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने की स्वतंत्रता दी गई थी।

5. प्रतिवादी-राज्य द्वारा उपरोक्त दिनांकित 27.09.2004 निर्णय की चुनौती को विद्वान जिला न्यायाधीश, गुड़गांव द्वारा खारिज कर दिया गया था और यह अंतिम रूप ले चुका है। अपीलकर्ता ने दिनांकित 27.09.2004 के फैसले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) गुड़गांव द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में, 07.01.2005 को प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक, गुड़गांव रेंज के समक्ष एक समेकित अभ्यावेदन को प्राथमिकता दी। पुलिस महानिरीक्षक, गुड़गांव रेंज, गुड़गांव ने 28.01.2005 दिनांकित आदेश के माध्यम से सभी प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया।इसके बाद, अपीलकर्ता को पुलिस महानिदेशक, हरियाणा से दिनांक 05.09.2006 का एक कारण दिखाएँ नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि टिप्पणी को हटाकर अपीलार्थी को अनुचित लाभ दिया गया था और उसे क्यों बहाल नहीं किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित किया जाना चाहिए, जिससे संकेत मिलता है कि इन प्रतिकूल टिप्पणियों के निष्कासन के कारण, वह अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त होने से बच गया था और आगे की पदोन्नति के लिए भी पात्र हो गया था।अपीलकर्ता ने 22.09.2006 को कारण बताओ नोटिस के लिए अपना जवाब दाखिल किया। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने दिनांक 30.10.2006 के आदेश द्वारा उपरोक्त अवधि के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (जिसे इसके बाद "एसीआर" (एकवचन में) और "एसीआर(स)" (बहुवचन में) के रूप में संदर्भित किया जायेगा) के पुनर्निर्माण का निर्देश दिया।

6. दिनांक 30.10.2006 के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2006 की सिविल रिट याचिका No.19128 दायर की।इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता को पुलिस अधीक्षक, मेवात, नूंह द्वारा दिनांक 08.09.2008 द्वारा जारी सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें उसे सूचित किया गया कि विभाग को जनहित में 55 वर्ष की आयु से अधिक की सेवा की आवश्यकता नहीं है और उसे पंजाब सिविल सेवा नियम, 1934 के रूल 8.18 के खंड-I भाग I और पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 3.26 (d) के संदर्भ में हरियाणा राज्य के तहत सेवा से सेवानिवृत्त होना था, जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है।इसके बाद पुलिस अधीक्षक, पलवल के दिनांकित 27.10.2008 के आदेश से 30.11.2008 से उनकी सेवानिवृत्ति का निर्देश दिया।विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2006 की सिविल रिट याचिका No.19128 **[2010 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 1193]** में दिनांक 27.01.2010 के फैसले

द्वारा रिट याचिका की अनुमति दी और प्रतिकूल एसीआर और अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पुनर्निर्माण के आदेश को रद्द कर दिया गया।विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता सभी परिणामी लाभों का हकदार था। उक्त निर्णय[1] [[1]यह उद्धरण एस. सी. सी. ऑनलाइन संस्करण से है।यह ध्यान दिया जाता है कि राम निवास (ऊपर) से उद्धृत भाग व्याकरणिक रूप से गलत प्रतीत होता है।] के प्रासंगिक भाग में कहा गया हैः

...

"मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। इन रिट याचिकाओं में शामिल विवाद को अमरजीत कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य, **1988 (4)** एस. एल. आर. **199** के मामले में एक फैसले और सी. डब्ल्यू. पी. सं. **2006** का **8356** (राम निवास बनाम हरियाणा राज्य) में डिवीज़न बेंच के निर्णय दिनांक 26.05.2006 से और राठी अलॉयज एंड स्टील लिमिटेड बनाम सी.सी.ई (1990) 2 एससीसी 324 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भी कवर किया जाता है। राम निवास (सुपरा) के मामले में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैंः

> ".... सबसे पहले, कानून में प्रशासनिक पदानुक्रम है जो सम्मान नहीं होना चाहिए और कोई भी उत्तराधिकारी अपने पूर्ववर्ती द्वारा पारित आदेश को दरकिनार नहीं कर सकता है।दूसरा, पंजाब पुलिस नियम, 1934 के तहत कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि हरियाणा पर लागू होता है या किसी भी निर्देश या अधीनस्थ कानून में कार्यालय में पूर्ववर्ती द्वारा पारित आदेश की समीक्षा का प्रावधान नहीं है।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि शक्ति या समीक्षा का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि यह क़ानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है।इस संबंध में राठी एलॉयज एंड स्टील लिमिटेड बनाम सी.सी.ई., **(1990) 2** एससीसी **324** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जा सकता है। हमारे विचार को अमरजीत कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 1988 (4) एस. एल. आर. 199 के मामले में इस न्यायालय के फैसले से भी समर्थन मिलता है। "

उपरोक्त निर्णय के बाद, सी. डब्ल्यू. पी. नं. 2007 का 9973 और सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2007 के 12095 को इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ द्वारा दिनांक 23.3.2009 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। इन सभी निर्णयों का अनुपात यह है कि सेवा के पदानुक्रम में एक अधिकारी के

पूर्ववर्ती को अपने आदेशों की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है। "

(sic)

7. स्पष्ट रूप से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि मूल निष्कासन को अवैध नहीं माना जा सकता है, और उनके द्वारा निर्दिष्ट कानून की घोषणाओं को देखते हुए टिप्पणियों का बाद में पुनर्निर्माण गलत होगा।

8. प्रतिवादी-राज्य, पीड़ित, 2011 (ओ एंड एम) की लेटर्स पेटेंट अपील 406 को प्राथमिकता देता है, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश के 27.01.2010 के फैसले को दरकिनार करते हुए दिनांक 25.04.2011 **[2011** एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच **4687]** के फैसले द्वारा अनुमति दी गई थी, जिससे हरियाणा के पुलिस महानिदेशक के दिनांक 30.10.2006 के आदेश को बहाल किया गया।विद्वत खंड पीठ के फैसले पर हमारे सामने आक्षेपित है।

<u>अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुतियाँः:</u>

9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय इस कारण से अस्थिर है कि प्रतिवादी-राज्य की अपील को अनुमति देने का मुख्य आधार यह था कि पुलिस महानिरीक्षक का दिनांक 28.01.2005 का आदेश पूरी तरह से विद्वान सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ था, जो प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने से इनकार कर रहा था, जो न केवल अत्यधिक अनुचित था, बल्कि पूरी तरह से अनुचित था और पुलिस महानिदेशक ने अपने अधीनस्थ के आदेश को सही ढंग से रद्द कर दिया।यह प्रस्तुत किया गया कि विद्वान खंड पीठ इस बात पर विचार करने में विफल रही कि पुलिस महानिदेशक के पास पंजाब पुलिस नियम, 1934 के अनुसार समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है जो हरियाणा राज्य पर लागू होती है।

10. इसके अलावा, यह दोहराते हुए कि राज्य की अपील को अनुमति देने के लिए विद्वान खंड पीठ का मूल तर्क, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह था कि विद्वान दीवानी न्यायालय ने नियंत्रक अधिकारी द्वारा पारित टिप्पणियों को हटाने में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और इस प्रकार, पुलिस महानिरीक्षक को हटा देने के लिए आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं था, अत्यधिक अनुचित और पूरी तरह से अनुचित था। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इसी तरह की परिस्थितियों में, एक समन्वित एकल पीठ ने यह ठहराने के लिए हस्तक्षेप

किया था कि पुलिस महानिदेशक के पास पूर्ववर्ती-कार्यालय द्वारा पारित आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं था।

<u>आधिकारिक प्रतिवादीगण-आर1 से आर7 की तरफ से प्रस्तुतियाँ:-</u>

11. इसके विपरीत, हरियाणा राज्य के विद्वान अधिवक्ता और अन्य आधिकारिक प्रतिवादीगण (आर2, आर3, आर4, आर5, आर6 और आर7) ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले को 11 साल की अत्यधिक देरी के बाद फिर से दायर किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि भले ही देरी का आधार समझाया जाना चाहिए, अपीलकर्ता के बेटे की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने के कारण, वही 2011 में हुआ था और इस प्रकार, इस तरह की घटना के 10 साल बाद, केवल 2022 में फिर से दाखिल किया गया था, जो अपीलकर्ता को इतनी लंबी और अस्पष्टीकृत देरी के लिए माफी का पात्र नहीं बनाएगा ।उन्होंने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण, कि पुलिस महानिरीक्षक विद्वान दीवानी न्यायालय के फैसले तक अधिक नहीं पहुंच सकते थे, सही है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता के ए. सी. आर. में प्रतिकूल प्रविष्टि गंभीर आरोपों जैसा की भ्रष्टाचार, अवज्ञा और कर्तव्य की अवहेलना के कारण थी। ।

12. विद्वान अधिवक्ता ने यह रुख अपनाते हुए अपनी दलीलों का सारांश दिया कि अपीलकर्ता अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने के कारण, 'सजा' नहीं होने के कारण, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होंगे।

<u>विश्लेषण, कारण और निष्कर्ष:</u>

13. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय इस बात पर ध्यान देगा कि विद्वान एकल न्यायाधीश और विद्वान खंड पीठ दोनों ने तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के सही परिप्रेक्ष्य में कानूनी स्थिति की सराहना नहीं की।

14. निर्विवाद स्थिति यह है कि विचाराधीन अवधियों के लिए अपीलार्थी के ए. सी. आर. में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की गई थी, जिसके कारण शुरू में एक शिकायत के आधार पर विभागीय जांच का आदेश पारित किया गया था; विभागीय जांच में, एक आदेश पारित किया गया था, और अपीलकर्ता को हेड कांस्टेबल के पद से कांस्टेबल के पद पर वापस कर दिया गया था।अपीलकर्ता ने इस तरह के प्रत्यावर्तन को चुनौती दी।प्रत्यावर्तन क्रम को एक वृद्धि रोककर संशोधित किया गया था।प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने के लिए, वह पुलिस महानिरीक्षक, गुड़गांव रेंज के समक्ष गए, जिसे शुरू में पूरी अवधि के लिए खारिज कर दिया गया था।आगे के अभ्यावेदन पर,

पुलिस महानिरीक्षक, गुड़गांव रेंज ने 20.07.2002 को, 01.04.2000 से 29.12.2000 की अवधि के लिए टिप्पणियों को आंशिक रूप से हटा दिया।

15. अपीलकर्ता ने एक वेतनवृद्धि पर रोक लगाने के आदेश के साथ-साथ अपने ए. सी. आर. में प्रतिकूल प्रविष्टियां/टिप्पणी (ओं) के खिलाफ सिविल सूट नंबर 168 ऑफ 2002 दायर किया, जिसका अंत में विद्वान दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग), गुड़गांव द्वारा एक वेतनवृद्धि पर रोक लगाने में हस्तक्षेप करते हुए, लेकिन ए. सी. आर. पहलू में हस्तक्षेप नहीं करते हुए, दिनांक 27.09.2004 के निर्णय और आदेश द्वारा निर्णय लिया गया। हालाँकि, उक्त निर्णय में, यह निम्नानुसार देखा गया थाः

> "यदि बिल्कुल भी, वादी को लगता है कि टिप्पणी दर्ज करना उपरोक्त प्रतिकूल विभागीय कार्यवाही और उसके परिणाम का परिणाम था, तो इस अदालत द्वाराआक्षेपित आदेश को दरकिनार करने के मद्देनजर, वादी, यदि इस तरह से सलाह दी जाती है, तो प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी के साथ फिर से एक अभ्यावेदन दायर कर सकता है, जिसका निर्णय उक्त प्राधिकारी द्वारा शीघ्रता से किया जाएगा। परिस्थितियों की समग्रता में, यह न्यायालय वादी के ए. सी. आर में प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है।इसलिए, वादी के पक्ष में प्रतिकूल टिप्पणियों के निष्कासन के संबंध में कोई भी राहत नहीं दी जा सकती है।तदनुसार, मुद्दा न. 2 वादी के खिलाफ और प्रतिवादियों के पक्ष में तय किया जाता है।"

(sic)

16. इसने अपीलकर्ता को प्रतिकूल टिप्पणियों के निष्कासन के लिए पुलिस महानिरीक्षक, गुड़गांव रेंज के समक्ष फिर से एक अभ्यावेदन दायर करने की अनुमति दी, जिसका अनुकूल निपटारा किया गया और प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा दिया गया।हालाँकि, पुलिस महानिदेशक ने अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि प्रतिकूल टिप्पणियों को गलत तरीके से हटा दिया गया था, जिससे अपीलकर्ता अनिवार्य सेवानिवृत्ति से बच गया। इसके बाद, अपीलकर्ता को पंजाब सिविल सेवा नियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी को इस तरह की शक्ति प्रदान किए जाने के संदर्भ में 55 वर्ष की आयु को पार करने के बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया।इसके बाद मामला उच्च न्यायालय के समक्ष आया, शुरू में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, जिन्होंने कुछ उदाहरणों पर भरोसा करते हुए दर्ज किया कि पुलिस

महानिदेशक उसमें आक्षेपित आदेश पारित नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह उनके पूर्ववर्ती द्वारा पारित आदेश की समीक्षा के बराबर था।

17. न्यायालय इस मोड़ पर यह इंगित करने के लिए रुक जाएगा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उल्लिखित तथ्यात्मक आधार स्वयं गलत था, क्योंकि यह पुलिस महानिरीक्षक थे, जिसने अपने पूर्ववर्ती द्वारा पारित एक आदेश की 'समीक्षा' की थी-कार्यालय में प्रतिकूल टिप्पणियों को हटा कर, जिसे पहले उनके पूर्ववर्ती-कार्यालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। पंजाब पुलिस नियम, 1934 के खंड II में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैंः

> **"16.28.** कार्यवाही की समीक्षा करने की शक्तियाँ
>
> (1) महानिरीक्षक, एक उप महानिरीक्षक और एक पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थों द्वारा दिए गए अवाड्र्स के अभिलेखों की मांग कर सकते हैं और उनकी पुष्टि, वृद्धि, संशोधन या रद्द कर सकते हैं, या आगे की जांच कर सकते हैं या आदेश पारित करने से पहले ऐसा करने का निर्देश दे सकते हैं।
>
> (2) यदि बर्खास्तगी का कोई अधिनिर्णय रद्द कर दिया जाता है, तो इसे रद्द करने वाला अधिकारी बताएगा कि क्या इसे निलंबन के बाद बहाली माना जाना है या नहीं।आदेश में यह भी बताया जाना चाहिए कि बर्खास्तगी से पहले की सेवा को पेंशन के लिए गिना जाना चाहिए या नहीं।
>
> (3) उन सभी मामलों में जिनमें अधिकारी किसी अवार्ड को बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं, वे अंतिम आदेश पारित करने से पहले संबंधित चूककर्ता को व्यक्तिगत रूप से या लिखित रूप में कारण दिखाने का अवसर देंगे कि उसकी सजा क्यों नहीं बढ़ाई जानी चाहिए।
>
> (जोर दिया गया)

18. स्पष्ट रूप से, नियम 16.28 में विचार की गई 'समीक्षा' एक वरिष्ठ प्राधिकारी को अपने अधीनस्थों द्वारा दिए गए अवाड्र्स के रिकॉर्ड की मांग करने और उनकी पुष्टि करने, बढ़ाने, संशोधित करने या रद्द करने, या आगे की जांच करने या आदेश पारित करने से पहले ऐसा करने का निर्देश देने का अधिकार देती है। 'इस प्रकार,' समीक्षा 'एक उच्च प्राधिकारी द्वारा की जाती है न कि एक ही प्राधिकारी द्वारा।

19. गुणों की ओर ध्यान देने से पहले, हम तुरंत उस विसंगति को उजागर कर सकते हैं जो कानूनी रूप से और वास्तव में समय बीतने के कारण नियमों (उपरोक्त) में आई है। न्यायिक या कानूनी रूप से प्रशिक्षित मस्तिष्क के लिए, यह स्पष्ट है कि 'समीक्षा' का एक विशिष्ट अर्थ है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है।सीधे शब्दों में कहें तो समीक्षा उसी प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश पर पुनर्विचार है जिसने मूल आदेश पारित किया था, चाहे वह अदालत हो या कार्यकारी अधिकारी।उपरोक्त नियम का शीर्षक एक गलत नाम है क्योंकि 'समीक्षा' की कोई शक्ति नहीं बनाई गई है या प्रदान नहीं की गई है, जैसा कि नियम 16.28 के (1), (2) और (3) के पठन से प्रकट होता है।पूर्णता के लिए, नियम 16.29 "अपील का अधिकार" का हकदार है और नियम 16.32 को "संशोधन" लेबल किया गया है।यह मुद्दे का एक हिस्सा है।

20. अगला भाग यह है कि मूल रूप से 1934 में बनाए गए नियमों में अधिकारियों को "महानिरीक्षक, एक उप महानिरीक्षक और एक पुलिस अधीक्षक" के रूप में माना गया था। उस समय के "महानिरीक्षक" (जब सेवा को इंपीरियल/भारतीय पुलिस कहा जाता था) राज्य पुलिस का नेतृत्व करते थे, लेकिन आज राज्य पुलिस के पदानुक्रम में कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस महानिदेशक के रूप में जाना जाता है, जो भारतीय पुलिस सेवा से लिया गया एक अधिकारी होता है, जो राज्य पुलिस तंत्र के शीर्ष पर बैठता है। वास्तव में, आज पुलिस महानिरीक्षक प्रशासनिक रूप से पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ हैं।

21. ये नियम ऐसे समय में भी बनाए गए थे जब रेंज और आयुक्तालयों की प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी।निस्संदेह, नियम, बेहतर या बदतर के लिए (बदतर, हम जोखिम उठाते हैं) समय के साथ तालमेल नहीं रखते हैं।हम इस बात की सराहना नहीं करते हैं कि संबंधित अधिकारी भ्रम को दूर करने के लिए कम से कम पदों के सही आधिकारिक विवरण के साथ नियमों को अद्यतन/संशोधित करने में असमर्थ क्यों हैं।

22. वर्तमान मामले में, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा ने पहले कभी कोई आदेश पारित नहीं किया था और पहली बार जब इस मुद्दे को उनके संज्ञान में लाया गया था, तो अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि प्रतिकूल टिप्पणियों का पुनर्निर्माण क्यों नहीं किया जाना चाहिए; क्योंकि इस तरह के निष्कासन के कारण, वह अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त होने से बच गया था।
इस प्रकार, 2007 के सी. डब्ल्यू. पी न.9973 और 2007 के सी. डब्ल्यू. पी न.12095 दिनांक 23.03.2009 में विद्वान समन्वय एकल न्यायाधीश द्वारा

पारित आदेश वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं था। चाहे जो भी हो, हरियाणा राज्य ने यहां विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील की, जिसे प्रतिवादी-राज्य के पक्ष में अनुमति दी गई थी।

23. इस न्यायालय ने पाया कि विद्वत खंड पीठ ने इस मुद्दे पर उस तरीके से संपर्क नहीं किया है जिसकी उसे आवश्यकता थी।विद्वान एकल न्यायाधीश के दृष्टिकोण में हस्तक्षेप के लिए दिया गया कारण यह है कि पुलिस के महानिरीक्षक के लिए प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाना अत्यधिक असंभव और अनुचित था, जब विद्वान दीवानी न्यायालय द्वारा ऐसा करने से इनकार करने वाला न्यायिक निर्णय आया था। उक्त तर्क का उपयोग इस तथ्य पर ध्यान देने के बावजूद किया गया था कि भले ही समीक्षा की कोई शक्ति थी, मौजूदा परिस्थितियों में, यह पूरी तरह से मनमाना था।यह भी कहा गया कि विद्वान दीवानी न्यायालय के न्यायिक फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए था।यह न्यायालय ध्यान देगा कि इस तरह का तर्क भी गलत है।तथ्य यह रहा कि, सही या गलत, विद्वान सिविल न्यायालय ने अपीलकर्ता को प्रतिकूल टिप्पणियों के निष्कासन के लिए फिर से आगे बढ़ने का अवसर दिया था, जो अपीलकर्ता ने किया था।यह कहने के बाद, यह न्यायालय अब इस मुद्दे को पूरी तरह से कानूनी दृष्टिकोण से देखेगा-पहला, अधिकारी क़ानून द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग कर रहे थे, और दूसरा, कोई भी आदेश जो उसी प्राधिकरण द्वारा पहले के आदेश की 'समीक्षा' (शब्द के कानूनी अर्थ में) के बराबर है, तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक कि विशेष रूप से प्रासंगिक क़ानून द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है।

24. इसके अलावा, विद्वान सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) ने प्रतिकूल टिप्पणियों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया, फिर भी अपीलकर्ता को उसके निष्कासन के लिए आगे बढ़ने की स्वतंत्रता प्रदान की।पंजाब पुलिस नियम, 1934 में इस तरह के किसी भी प्रावधान के अभाव में, विद्वान दीवानी न्यायालय ने यह मानते हुए गलती की कि उसके पास ऐसा करने की शक्ति है।ऐसे मामले हो सकते हैं जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत एक उच्च न्यायालय या यह न्यायालय अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष रूप से किसी प्रतिनिधित्व पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दे सकता है, भले ही विशिष्ट प्रावधानों का अभाव हो।त्रिपुरा उच्च न्यायालय बनाम तीर्थ सारथी मुखर्जी, **(2019) 16** एस. सी. सी. **663** में, सवाल यह उठा कि क्या, एक वैधानिक प्रावधान के अभाव में, एक रिट याचिकाकर्ता परीक्षा उत्तर लिपियों का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है? जवाब देते हुए, इस न्यायालय ने कहाः

"20. हालाँकि सवाल यह उठता है कि क्या अधिकार के रूप में पुनर्मूल्यांकन की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होने पर भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं जो न्यायालय को किसी भी संदेह में छोड़ दें।कुछ परिस्थितियों में एक रिट आवेदक के साथ गंभीर अन्याय किया जा सकता है। मामला वहाँ उठ सकता है जहाँ पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, यह पता चलता है कि सही उत्तर देने के बावजूद कोई अंक नहीं दिए जाते हैं।इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह ऐसे मामले तक ही सीमित होना चाहिए जहां उत्तर की शुद्धता के बारे में कोई विवाद न हो।इसके अलावा, यदि कोई संदेह है, तो संदेह का समाधान उम्मीदवार के पक्ष में करने के बजाय परीक्षा निकाय के पक्ष में किया जाना चाहिए।अनुच्छेद 226 के तहत व्यापक शक्ति उपलब्ध बनी रह सकती है, भले ही ऐसी स्थिति में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है जहां एक उम्मीदवार के पास सही उत्तर देने के बावजूद और जिसके बारे में थोड़ा भी संदेह नहीं हो सकता है, उसे गलत उत्तर दिया गया माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप उम्मीदवार को किसी भी अंक से वंचित पाया जाता है।

21. यदि दूसरी परिस्थिति को रिट अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए, तो क्या रिट अदालत अपने पास शक्ति के विशाल भंडार के बावजूद असहाय हो सकती है?यह कहना एक बात है कि पुनर्मूल्यांकन के प्रावधान की अनुपस्थिति उम्मीदवार को अधिकार के रूप में मूल्यांकन के अधिकार का दावा करने में सक्षम नहीं बनाएगी और दूसरा यह कहना कि किसी भी परिस्थिति में जहां पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है, वहां रिट अदालत अपनी निस्संदेह संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी?हम दोहराते हैं कि स्थिति केवल दुर्लभ और असाधारण हो सकती है।"

(जोर दिया गया)

25. अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को दी गई शक्ति की अनूठी प्रकृति पर हाल ही में बी. एस. हरि कमांडेंट बनाम भारत संघ, **2023** एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. **413** में टिप्पणी की गई है। **संजय दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 610 में**, उस आदेश **में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए, एक कारण जिसका वजन था वह यह था कि एक उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया था, न कि सत्र न्यायालय ने।** इसने फिर से उच्च न्यायालयों की विशेष प्रकृति पर जोर दिया, जिसमें यह भी शामिल है कि वे संवैधानिक न्यायालय हैं।

26. इस प्रकार, विद्वान सिविल न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी कि अपीलकर्ता प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है, का अर्थ यह नहीं लिया जा सकता है कि अपीलकर्ता को उसी प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए कानूनी रूप से पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी। विद्वान दीवानी न्यायालय ने जिस बात पर ध्यान नहीं दिया वह यह थी कि उसके द्वारा सुझाए गए किसी भी प्रावधान ने कार्रवाई की अनुमति नहीं दी थी।दूसरे चश्मे से जाँच करने पर, भले ही हम अपीलकर्ता के पक्ष में विद्वान सिविल कोर्ट के दृष्टिकोण को पढ़ते हों, हो सकता है कि उनके पास पुलिस महानिदेशक, हरियाणा से संपर्क करने का कुछ औचित्य था, क्योंकि वे एक बेहतर प्राधिकारी थे, लेकिन उसी प्राधिकारी से फिर से संपर्क नहीं किया जा सकता था।तर्क की इस पंक्ति पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि भले ही अपीलकर्ता के पास अधिकारियों के समक्ष फिर से जाने की गुंजाइश थी और वह विद्वान दीवानी न्यायालय के हस्तक्षेप न करने की निंदा करता है, लेकिन वही उच्च प्राधिकारी के लिए होना चाहिए था, न कि उसी प्राधिकारी के लिए, जिसने पहले निष्कासन से इनकार कर दिया था। किसी भी स्थिति में, हमें इस पर आगे विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।

27. 1971 में राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि बार-बार किए गए अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा क्योंकि यह सरकारी पत्र सं. 2784-3 S-70 दिनांक 22.03.1971 अनिवार्य करता है कि प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ दूसरा प्रतिनिधित्व झूठ नहीं होगा और जिसने इस स्थिति को स्पष्ट किया कि उसी प्राधिकरण के पास अपने पूर्ववर्ती-कार्यालय द्वारा पारित आदेश के लिए समीक्षा की कोई शक्ति नहीं थी।

28. इस प्रकार, पुलिस महानिदेशक ने अपीलकर्ता को उचित कारण दिखाया और उसके बाद कार्रवाई की।घटनाओं की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए, परिणामी कार्रवाई, हमारे विचार में, न्यायालय की अंतरात्मा को मनमाना या चौंकाने वाली नहीं कहा जा सकता है, ताकि हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। पुलिस की तरह वर्दीधारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति के लिए, उसकी सत्यनिष्ठा और आचरण से संबंधित प्रतिकूल प्रविष्टि का निर्णय उच्च प्राधिकारीयो द्वारा किया जाना है जो ऐसी प्रविष्टि को दर्ज और अनुमोदित करता है।पंजाब सिविल सेवा नियम, 1934 के तहत वैधानिक प्रावधानों के अनुसार इस तरह की टिप्पणियों वाले कर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाना, तत्काल तथ्यों में, ऐसी कार्रवाई नहीं है जिस पर यह न्यायालय हस्तक्षेप करना चाहेगा।इसलिए हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, हालांकि जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, पूरी तरह से अलग कारणों से जो विद्वान खंड पीठ द्वारा विचार किया गया था और प्रबल था।

29. तदनुसार, तत्काल अपील खारिज कर दी जाती है।

30. दलों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

<u>अतिरिक्त निर्देश (एस):</u>

31. इस निर्णय की प्रतियां (ए) चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकारों के मुख्य सचिवों को; (बी.1) प्रधान सचिव, गृह और न्याय विभाग, पंजाब सरकार और (बी. 2) अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, हरियाणा सरकार और (सी) रजिस्ट्री द्वारा पंजाब और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों को भेजी जानी चाहिए।

32. पैराग्राफ 19 से 21 में दर्ज टिप्पणियों के अनुरूप तुरंत कदम उठाए जाएं।

...... जे.

[विक्रम नाथ]

......जे.

[अहसानुद्दीन अमानुल्लाह]

नई दिल्ली

14 जून, 2023

अस्वीकरण:– स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्येश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।